प्रश्न: "भारत की प्रगति के पिछले पचास वर्ष योजना आधारित थे, परन्तु प्रगति के अगले पचास वर्ष बाजार द्वारा संचालित रहेंगे।" आलोचना कीजिए। (250 शब्द)

उदारीकरण के पूर्व योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की आवश्यकता :-

उत्तर: स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत का लक्ष्य एक समाजवादी समाज की स्थापना करना था। चूँकि स्वतंत्र भारत को विरासत में गरीबी और पिछड़ापन जैसी अन्य समस्याएँ मिली; अत: मानवतावादी प्रकृति और सामूहिकता के दृष्टिकोण से संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण कर लोकतंत्रात्मक समाजवाद की स्थापना हेतु भारत में नियोजन की नीति अपनाई गई। भारत में नियोजन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है, अत: इसके लिए पूँजीनिर्माण की दर, आय के स्तर में वृद्धि और बचत तथा निवेश की दर में वृद्धि हेतु योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई।

प्रगति के मापक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद एवं अन्य संकेतकों को बेहतर बनाने में योजना द्वारा किये गए कार्य :-

प्रगति के मापक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद एवं अन्य संकेतकों को बेहतर बनाने में विभिन्न योजनाओं द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किये गए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप पिछले 52 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय में औसतन 4.0 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय 2.0 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ती रही है। 1950 की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन में 3½ गुणा से अधिक वृद्धि हुई है। जहाँ पाँचवे दशक में विकास दर 3.5% थी, वह बढ़कर 6.0% हो गई है, साथ ही औद्योगिक वृद्धि दर बढ़कर 10% हो गई है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात 25% से कम रह गया है। विदेशी मुद्रा भंडार 140 अरब डॉलर से ऊपर पहुँच गया है और मुद्रा स्फीति की दर पर भी लगभग काबू पा लिया गया है। इस प्रकार पाँचवे दशक में 3.5% से वर्तमान में लगभग 6.5% सकल घरेलू उत्पाद हो गया है। स्पष्टत: यह सभी परिणाम भारत में नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था के प्रयास ही संभव हो सके हैं।

नये आर्थिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम :-

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप भारत में 1991 के बाद से आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए हैं। स्पष्टत: नई आर्थिक व्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण आयाम- उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण के तहत भारत की अर्थव्यवस्था को संचालित किए जाने का प्रयास प्रारंभ किए गए हैं।

बाजारी प्रक्रियाओं का महत्व :-

उपर्युक्त आर्थिक व्यवस्था के आयामों के तहत 'बाजार- अनुमुख अर्थव्यवस्था' का अत्यधिक महत्व है। भारत जैसी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था हेतु उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि के अतिरिक्त बाजारी प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। संसाधन आधारित सुधारवादी नियोजनों से बाजारी- प्रक्रियाओं को विनियमित करके ऐसे लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं।

Good

योजना में परिवर्तन कर उसे प्रासंगिक बनाने का प्रयास :-

भूमंडलीकरण के इस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था भी अपने को उसके अनुरूप समायोजित करने का प्रयास कर रही है। अत: भारत सरकार नियंत्रक से विनियामक की भूमिका का निर्वहन करते हुए उदारीकरण को बढ़ावा के क्रम में निजीकरण की ओर उन्मुख हो रही है। इस क्रम में पूँजी का अंतरप्रवाह और निवेश की दर को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही बाजारी प्रक्रियाओं को बढ़ावा हेतु अन्य सभी आर्थिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर उसे प्रासंगिक बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

निष्कर्ष :-

स्पष्टत: 21वीं सहस्राब्दि में प्रगति हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था में योजनागत और बाजारी प्रक्रियाओं का समेकन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

मुनव्वर
05/2/24